भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 218

दिनांक 06 अगस्त, 2024

किसानों की आय दोगुनी किए जाने से सम्बन्धित अध्ययन

***218. श्री सु. वेंकटेशन:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें ऐसे 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है जिन्होंने अपनी आय में दोगुनी से अधिक वृद्धि की है;

(ख) क्या 'किसानों की आय दोगुनी किया जाना (डीएफआई)' विषय के संबंध में कोई सरकारी अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितने प्रतिशत किसानों ने इसे प्राप्त किया;

(ग) क्या डीएफआई से संबंधित आंकड़े मुद्रास्फीति समायोजित हैं अथवा वास्तविक आय में वृद्धि हुई है; और

(घ) ग्रामीण किसानों के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) में 'आय दोगुनी किया जाना' किस प्रकार परिलक्षित हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा के पटल पर प्रस्तुत है।

****

"किसानों की आय दोगुनी किए जाने से सम्बन्धित अध्ययन" से संबंधित लोक सभा के दिनांक 06.08.2024 के तारांकित प्रश्न सं. 218 के भाग (क) से (घ) से संबंधित विवरण

(क): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने ''आजादी का अमृत महोत्सव'' के एक अंश के तौर पर एक पुस्तक जारी की है जिसमें 75,000 किसानों जिन्होंने अपनी आय को दोगुनी से भी अधिक बढ़ाया है, की सफल कहानियों का संकलन है। दस्तावेज में आय में वृद्धि के संबंध में दिया गया डाटा किसानों की प्रतिक्रिया पर आधारित है।

(ख) एवं (ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एक निश्चित अंतराल पर परिस्थिति मूल्यांकन सर्वे (SAS) किया जाता है। कृषि परिवारों की आय पर पिछले उपलब्ध अनुमान 77वें चक्र (जनवरी-दिसम्बर, 2019) के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा आयोजित किए गए कृषि परिवारों के परिस्थिति मूल्यांकन सर्वे पर आधारित हैं। सर्वे के अनुसार, NSS 70वां चक्र (2012-13) तथा NSS 77वां चक्र (2018-19) से हासिल प्रति कृषि परिवार अनुमानित औसत मासिक आय क्रमश: रुपए 6426/- तथा रुपए 10218/- है।

(घ): राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2022 से जुलाई, 2023 की अवधि के दौरान परिवार खपत व्यय सर्वे (HCES) का आयोजन किया गया। पिछला सर्वे वर्ष 2011-12 में किया गया था। इस सर्वे से परिवार का मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (MPCE) के अनुमान सृजित हुए और इसका वितरण राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों, तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लिए देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग था। सर्वे के अनुसार, वास्तविक रूप में वर्ष 2011-12 से 2022-23 तक ग्रामीण एवं शहरी भारत में मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (MPCE) क्रमश: 44 एवं 35 प्रतिशत तक बढ़ा।

****